स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, भोपाल और अन्य

अक्टूबर 20, 1967

[के.एन. वांचू, सी.जे, एम. हिदायतुल्लाह, जे, सी. शाह, आर. एस. बचावत, वी. रामस्वामी, जी. के. मित्टर और के. एस. हेगड़े, न्यायमूर्तिगण]

कराधान कानून (विलयित राज्यों तक विस्तार और संशोधन) 1949 का अधिनियम 67, धारा 6 द्वारा केंद्र सरकार को भुगतान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसे कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित आदेश विलयित राज्यों में भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अनुप्रयोग में लागू किया जाता है। यहाँ उचित ठहराने वाली आदेश के लिए संबंधित कराधान कानून (विलयित राज्य) (कठिनाइयों को दूर करना–संबंध) संशोधन आदेश, 1962 का आदान–प्रदान किया जाता है। यह आदेश करदाता को कानून द्वारा कर भुगतान से छूट प्राप्त होने के मामले में विलयित राज्यों में परिसंपत्तियों के अनुमानित मूल्यह्रास पर समझौता करने और लिखित मूल्य की गणना में ध्यान में रखने वाले होता है, जो इस आदेश की वैधता को निर्धारित करता है।

अपीलकर्ता कंपनी का गठन 1937 में भोपाल राज्य में किया गया था। उस राज्य के शासक द्वारा सभी के भुगतान से छूट दी गई थी। 31 अक्टूबर 1948 तक कर, भोपाल राज्य का विलय हो गया। 1 अगस्त 1949 को भारत के साथ। 1949 का अध्यादेश 21 और "कराधान कानून (विलयित राज्यों तक विस्तार और संशोधन) इसे प्रतिस्थापित करने वाले अधिनियम 67 1949 का प्रभाव पड़ा भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 को विलय तक विस्तारित करना राज्य। साथ ही संबंधित राज्य को निरस्त करना कानून। अध्यादेश और अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार को उचित आदेश पारित करने की शक्ति दी गई भारतीय अधिनियम को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना विलयित राज्य।

"कराधान कानून (विलयित राज्य) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1949 में यह प्रावधान किया गया कि इसके तहत कोई भी मूल्यांकन करने में भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 वास्तव में सभी मूल्यह्रास किसी विलयित राज्य से संबंधित किसी भी कानून या नियम के तहत अनुमति दी गई है आयकर और सुपर–टैक्स को ध्यान में रखा जाएगा के तहत मूल्यह्रास भत्ते की गणना । 10(2) (vi) (सी)और एस के अंतर्गत लिखित मूल्य । 10(5) (बी) भारतीय का आयकर अधिनियम, 1962 में ऐसा ही एक और आदेश पारित किया गया अर्थात् "कराधान कानून (विलयित राज्य) (हटाना)। कठिनाइयाँ) संशोधन आदेश, 1962। इसने "जटिलताओं के हटाने के आदेश, 1949" में एक विवरण जोड़ा। विवरण की ब) क्लॉज ने प्रदान किया कि जहां किसी मामले में आय को किसी कानून या नियम के तहत कर से मुक्त किया गया था जो एक विलय हुए राज्य में या राजा के साथ किए गए किसी समझौते के तहत, वहां, जहां आय ने कर के तहत छूट प्राप्त नहीं की गई थी, उस मामले में, जिसमें आय ने कर के तहत छूट नहीं प्राप्त की थी, उस ऐसे मामले में, जिसमें आय ने कर के तहत छूट नहीं प्राप्त की थी, वह छूट नहीं दी गई मानी जाएगी जो मूल मूल्यह्रास और लिखित मूल्य की गणना के उद्देश्य से वास्तविक रूप से छूट नहीं दी गई होती है। 1949–50 के मूल्यांकन वर्ष के लिए, आपील कंपनी को इसकी संपत्तियों के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लिया गया था और आगामी चार वर्षों में संपत्तियों की लिखित मूल्य उसी बुनियाद पर निर्धारित की गई थी। हालांकि, आयकर अधिकारी ने ध्यान देने के बाद ध्यान दिया कि व्यापार की शुरुआत से लेकर इसे कायम रखने पर आपीलन कंपनी को भारतीय राष्ट्रीय रूप से यह माना जाए कि उन्हें भोपाल आयकर अधिनियम के तहत मूल्यह्रास दिया गया था। इन आकलनों पर आयकर अधिकारी ने ध्यान दिया कि संविधान के अनुसार धारा 34 के तहत नोटिस जारी करने के बाद कर योग्य आय को पुनर्गणन की गई थी कि क्योंकि व्यापार

की शुरुआत से लेकर, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय रूप से यह माना जाएगा कि उन्हें भोपाल आयकर अधिनियम के तहत मूल्यह्रास दिया गया था। ये आकलन आपील कंपनी ने अधिनियम के तहत उचित प्राधिकारियों के सामक्ष चुनौती दी थी, लेकिन उस समय, जब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हुई थी, तब "जटिलताओं के हटाने के आदेश, 1962" जारी हो गए थे। "के. एस. वेंकटरामन एंड कंपनी (पी) लि. बनाम मद्रास राज्य, [1966] 2 एस.सी.आर. 229" में निर्णय के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने 1962 के आदेश की वैधता के संबंध में तर्क को नहीं माना। 2 एपीलेंट कंपनियों ने फिर लेख 226 के तहत संविधान की धारा 226 के अंतर्गत एक रिट पिटीशन दाखिल की।

उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया, और कंपनी ने प्रमाणपत्र के द्वारा इस महासभा में याचिका दाखिल की।

निर्धारित किया गया: (i) योग्यता की शर्त के रूप में कार्य करने या निर्देश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति जो चीजें प्रकट हो रही हैं, उन्हें साक्षात्कार की जाती है, सेंट्रल सरकार के लिए आवश्यक दिखाई देती है। 1949 के अध्यादेश की धारा 6 ने यह नहीं कहा कि काठिन्य के उत्थान होने की एक व्यक्तिगत संतोष की बात है; यह एक पूर्व–शर्त है कार्य के लिए और अगर यह शर्त उत्थान होने का चुनौती किया गया है, तो यह वस्तुनिष्ठ तथ्य के रूप में स्थापित होनी चाहिए।

कमीशनर ऑफ इनकम–टैक्स, हैदराबाद बहादुर रामगोपाल मिल्स लिमिटेड के खिलाफ [1961] 2 एस.सी.आर. 318 में स्पष्टीकरण दिया।

(ii) आदेश ने दावा किया कि उसे नहीं उत्पन्न हुई काठिनाई को दूर करने के लिए अंश दी गई थी, जिसका उत्थान नहीं हुआ था। यह यह बात कि न्यायालयों ने नहीं माना कि विभाजित राज्यों में कर से छूटे गए मामलों में अनुमानित कल्याण की गणना की जानी चाहिए, इस प्रकार की काठिनाई के लिए नहीं था, जिसके लिए धारा ६ के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था। यह भी संभावना नहीं थी कि इसमें शब्दों का उपयोग करना असंभव है s. 10(5) विधायित (बी) के साथ पढ़ा गया, जिसमें कहा गया था कि विलयित राज्यों में निबंधित निगम की संपत्ति की लिखित मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

1962 का आदेश अमान्य था क्योंकि धारा के तहत शक्ति के आह्वान को उचित ठहराने में कोई "कठिनाई" उत्पन्न नहीं हुई थी। 1949 के अधिनियम 67 का 6।

आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश बनाम स्ट्रे प्रोडक्ट्स लिमिटेड, [1966] 2 एस.सी.आर. 881, के.एस. वेंकटरमन एंड कंपनी (पी) लिमिटेड वी. मद्रास राज्य, [1966] 2 एस.सी.आर. 229, आयकर आयुक्त, बंबई वी. धरमपुर लेदर क्लॉथ कंपनी लिमिटेड, (19661 2 एस.सी.आर. 859, आयकर आयुक्त, बनाम कमला मिल्स लिमिटेड, (1949) 17·17 आई.टी.आर. 130· और वेंकदम लक्ष्मीनारायण· बनाम। आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश, (1961) 43 आई.टी.आर. 526. संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्र: सिविल अपील संख्या 303 वर्ष 1967।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तारीख 4 अप्रैल, 1966 की निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील।

ए.के. सेन, एच.आर. गोखले, रमेश्वर नाथ और महिंदर नारायण, जो अपीलकर्ता हैं।

नीरेन दे, अतिरिक्त सॉलिसिटर–जनरल, जी.आर. राजगोपाल, आर. गणपति अय्यर और आर.एन. साच्थे, जो प्रतिस्पर्धियों के लिए हैं।

नीरेन दे, अतिरिक्त सॉलिसिटर–जनरल और आर.एन. साच्थे, जो भारत के लिए वकील–महासचिव हैं।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति शाहा द्वारा दिया गया था–– इस मामले की सुनवाई इस महासभा के दिसंबर 3, 1965 को दिए गए एक निर्णय का परिणाम है: कमिशनर ऑफ इनकम– विद्युत, मध्य प्रदेश बनाम स्ट्राव प्रोडक्ट्स लिमिटेड (1)। (1)[1966] 2 एस.सी.आर. 881।

यह नियमितकर्ता अगस्त 1935 में अपनी स्थापना करी गई थी जिसका मुख्यालय भारतीय राज्य भोपाल में था, और 1939 में वह कागज के लपेटने के निर्माता के रूप में व्यापार शुरू किया। निवेदक ने भोपाल के महाराज से एक समझौते में दाखिला किया, जिसमें निवेदक को राज्य के सभी करों के भुगतान से मुक्ति दी गई थी, जो दस वर्षों तक थी और 31 अक्टूबर 1948 को समाप्त हो गई। भोपाल राज्य ने 1 अगस्त 1949 को भारत से विलीन हो गया। इस क्षेत्र को मुख्य आयुक्त क्षेत्र में रूपांतरित किया गया और बाद में 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश राज्य में विलीन कर दिया गया। भारत के गवर्नर–जनरल ने "कर विधियाँ (विलीन राज्यों के लिए विस्तार) अध्यादेश" 21 ऑफ 1949 जारी किया था ताकि कुछ कर विधियाँ विलीन राज्यों में लागू की जा सकें। इस अध्यादेश की धारा 3 के अनुसार, अन्य अधिनियमों के साथ–साथ, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 और इसके तहत जारी की गई सभी आदेश और नियम विलीन राज्यों में लागू किए गए और धारा 7 के अनुसार, विलीन राज्यों में लागू सम्बंधित कानूनों को रद्द कर दिया गया। धारा 8 के अनुसार, केंद्र सरकार को विलीन राज्यों में इस अध्यादेश की प्रावधानों को प्रारंभ करने में उत्पन्न कोई भी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक महसूस होने पर प्रावधान बनाने या निर्देश देने का अधिकार था। इस अध्यादेश का 21 ऑफ 1949 को रद्द कर दिया गया और इसे "कर विधियाँ (विलीन राज्यों के लिए विस्तार और संशोधन) अधिनियम" 67 ऑफ 1949 ने बदल दिया। इस अधिनियम की धारा 3 ने 1 अप्रैल 1949 से विलीन राज्यों में भारतीय आयकर अधिनियम और इसके तहत जारी किए गए सभी अधिनियमों को विस्तारित किया, और धारा 7 ने कहा कि धारा 3 में उल्लिखित अधिनियमों के सम्बंध में विलीन राज्यों में लागू कानूनों को रद्द कर दिया गया। धारा 6 ने प्रावधान किया:

> "यदि किसी ऐक्ट, नियम या आदेश की प्रावधानों को प्रारंभ करने में कोई कठिनाई आती है जो धारा 3 द्वारा विलीन राज्यों में विस्तारित की गई, तो केंद्र सरकार आदेश देने के लिए ऐसे प्रावधान बना सकती है या ऐसे निर्देश दे सकती है जो उसे आवश्यक महसूस होते हैं ताकि वे कठिनाई को हटाने के लिए हों।"

भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की प्रासंगिक प्रावधान हैं जो व्यवसाय चलाने के लिए निवेदक द्वारा प्रयुक्त भूखंड, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर की खराबी के निर्धारण में संबंधित हैं:

धारा 10, उपधारा 1: "कर व्यापार, पेशेवर या व्यवसाय के लाभों और आयों के लिए" विभाग में किसी व्यवसाय, पेशेवर या व्यवसाय के लाभ या आय के संदर्भ में निवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(2) इन लाभों या आयों की गणना के बाद, निम्नलिखित छूट दी जाएगी, अर्थात:

(vi) निवेदक की संपत्ति होने वाली इनमें से किसी भी भूखंड, मशीनरी, प्लांट, या फर्नीचर की खराबी के संदर्भ में, उनके मूल लागत पर उनके लिए प्रायः नौकों को छोड़कर, एक ऐसी धनराशि जो अनुमोदित मामले या वर्ग में किया जा सकता है, या अन्य मामलों में, उनकी लिखित बूंदे मूल्य के लिए उनके लिए निर्धारित मामले या वर्ग में किया जा सकता है। . . . . .

परंतु यह निर्धारित है–

(a). . . . . .

(b) . . . . . .

(c) इस अधिनियम या यहां रद्द किए गए किसी भी अधिनियम के तहत या 1886 के भारतीय आयकर अधिनियम के तहत, ऐसे सभी छूटों का योग किया जाएगा, जो निम्नलिखित मामले में दिए गए हों, और किसी मामले में भी, यहां तक की निवेदक के भूखंड, मशीनरी, प्लांट, या फर्नीचर की मूल लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए;"

"'लिखित मूल्य' का अर्थ धारा 10(5) में परिभाषित किया गया था जो जितना यह लागू है, यह प्रदान करता है:"

उप–धारा (2) में . . . . . 'लिखित बूंदे मूल्य' का अर्थ है –

(a) पिछले वित्य वर्ष में प्राप्त संपत्तियों के मामले में, निवेदक के वास्ते वास्तविक लागत:

प्रावधान . . . . .

(b) पिछले वित्य वर्ष से पहले प्राप्त संपत्तियों के मामले में, निवेदक के वास्ते वास्तविक लागत से कम, जिसमें भारतीय आयकर अधिनियम, 1886, थे, तब जारी निष्प्रेषित आदेशों के तहत उन्हें वास्तविक रूप से प्रदान की गई किसी भी आयकर या इसके अधिनियम के तहत निवेदक के द्वारा प्राप्त की गई सभी खराबी को कम करके:

प्रावधान . . . . . .

प्रावधान . . . . . .

विलीन राज्यों में कर विधियाँ भारतीय आयकर अधिनियम द्वारा नहीं रद्द की गई थीं: उन्हें भारतीय आयकर अधिनियम के विस्तार और संशोधन अधिनियम 1949 के अधीन रद्द कर दिया गया था। आयकर अधिनियम 1922 के योजना के प्रयोग में, निर्धारित विघटन अनुमतिद्वारा स्पष्ट रूप से कठिनाईयाँ उत्पन्न हुईं। आयकर अधिनियम के साफ शब्दों में, किसी निर्धारित करने के लिए एक निवेदक की करने की प्रदत्त खराबी ही ली जा सकती थी: इस अधिनियम के तहत प्रदत्त खराबी, या उन अधिनियमों के तहत जो विलिन हो गए थे, या भारतीय आयकर अधिनियम, 1886 के तहत जारी किए गए कार्यकारी आदेशों के तहत निवेदक द्वारा वास्तविक रूप से प्रदत्त की गई थी, वही लिया जा सकता था: राज्य कानूनों के अनुसार प्रदत्त करार को लिया नहीं जा सकता था। इसलिए केंद्र सरकार ने इस प्राधिकरण का प्रयोग करते हुए आयाद 21 ऑफ 1949 के विधायिका 8 के तहत "कर विधियाँ" (विलीन राज्यों) (कठिनाईयों के हटाए जाने) आदेश, 1949" जारी किया। उस आदेश के धारा 2 के अनुसार, यह प्रदान किया गया था:

> “भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत किसी भी मूल निधारित करने में, विलीन राज्य के आयकर और सुपर–टैक्स से संबंधित किसी भी कानून या नियम द्वारा वास्तविक रूप से प्रदत्त खराबी को जितना भी अनुमति दी गई है, उसे गणना में लिया जाएगा जो उपधारा (2) के प्रावधान (सी) के संदर्भ में योजना दी गई संपूर्ण खराबी भुगतान में होती है, और धारा 10 के उप–धारा (5) के प्रावधान (बी) के तहत लिखित मूल्य में होती है।
>
> परंतु यह निर्धारित है कि जिस मूल के संबंध में, किसी वर्ष में दोनों विलीन राज्य में और ब्रिटिश भारत में की गई हो, उस मूल के संबंध में, उन दोनों सं की माने जाने वाली दो सं में से, जिससे अधिक मूल दिया गया है, वही लिया जाएगा।"

1949 के कर विधियाँ (विलीन राज्यों के लिए विस्तार और संशोधन) अधिनियम की धारा 67 के उप–उपधारा (1) द्वारा आदेश 21 ऑफ 1949 को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन उस धारा के उप–उपधारा (2) के आदान प्रदान के आदान प्रदान के बल पर, विघटन की आदेश बनी रही। यह आदेश स्पष्ट उद्देश्य से बनाया गया था कि विलीन राज्यों के अधिनियमों के तहत प्रादात्त खराबी को "वास्तविक रूप से प्रदत्त" के रूप में गणना करने के लिए लिया जाए, ताकि भारतीय आयकर अधिनियम को विलीन राज्यों में निवेदकों के लिए प्रभावित किया जा सके। निवेदक द्वारा व्यापार चलाने के लिए लागू करने के लिए आयकर वर्ष 1949–50 के लिए उनके द्वारा दी गई खराबी को ध्यान में रखते हुए लाभ और व्यापार के लाभ की गणना करते समय, धारा 10(2)(vi) के अनुसार प्रादात्त खराबी को निवेदक के द्वारा निम्नलिखित भूखंड, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर की मूल लागत के एक प्रतिशत के रूप में लिया गया, और चार पछले आयकर वर्षों में निवेदक के द्वारा प्रदत्त खराबी के योग्यता के अनुसार मूल्य निर्धारित किया गया। इसके बाद, भोपाल के आयकर अधिकारी ने भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अनुसार धारा 34(1)(b) के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया आरंभ की, जिसके अनुसार निवेदक के संबंध में 1952–53 और 1953–54 के आयकर वर्षों के लिए। और 3 मार्च, 1958 को तारीख द्वारा आदेश जारी कर, आदेश किया कि क्योंकि व्यापार की शुरुआत से, निवेदक को भोपाल आयकर अधिनियम के तहत खराबी दी गई मानी जानी चाहिए। इसके बाद, आपीली असिस्टेंट कमीशनर और आयकर अपील ट्रिब्यूनल ने आयकर अधिकारी से असहमति और मूल मूल्यांकन को पुनर्स्थापित किया। आपील ट्रिब्यूनल के द्वारा की गई संदर्भन पर, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने निवेदक के पक्ष में फैसला दिया।

न्यायालय में आयकर आयुक्त द्वारा दाखिल की गई एक अपील की प्रक्रिया चल रही थी, तब केंद्र सरकार ने 1949 के अधिनियम की धारा 6 के अधिकार में एक आदेश जारी किया, जिसे "कर विधि (एकीकृत राज्य) (संघटनों के निवारण) संशोधन आदेश, 1962" कहा गया, और इसने निम्नलिखित स्पष्टीकरण को हटाने के लिए प्रस्तावना 2 के व्याख्यान में निम्नलिखित को जोड़ा:

> "स्पष्टीकरण.– इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिए, 'मिलिट राज्य' के किसी भी विधिया या नियमों द्वारा वास्तविक रूप से प्रदत्त सभी खपत का अवशिष्ट भाता' यह अर्थ रखता है और हमेशा से इसका मतलब माना जाता है:
>
> (ए) किसी भी विधिया या एक मिलिट राज्य में प्रयुक्त किये गए किसी भी नियमों के प्रावधानों के तहत लिखित मूल्य की गणना में ध्यान में लिये गए खपत का सम्मिश्र भाता और
>
> (ब) उन मामलों में जहाँ किसी मिलिट राज्य में या किसी समझौते के तहत किसी भी नियमों या नियमों के तहत कोई आयकर से यात्री निकाला गया था, जिसमें खपत की अनुमति नहीं दी गई थी, उसकी खपत जो अनुमति दी गई होती अगर उस आयकर से यात्री निकाला नहीं गया होता।"

न्यायालय ने आयकर आयुक्त द्वारा दाखिल की गई अपील में यह निर्णय दिया कि "वास्तविक रूप से प्रदत्त" अभिव्यक्ति जिसे 1949 के 'संघटनों के निवारण आदेश' में उपयोग किया गया था, उसका अर्थ था कि वास्तविक भाता जो प्रदत्त किया गया था, लेकिन 1962 के 'कर विधि (एकीकृत राज्य) (संघटनों के निवारण) संशोधन आदेश' द्वारा जो व्याख्या जोड़ी गई थी, उस विवरण के आधार पर, दरकारी निवेशियों के लिखित मूल्य की गणना के लिए योग्य आधार को आयकर अधिकारी ने अपनाया था। यहां यात्री के पक्षकार ने 'कर विधि (मिलिट राज्य) (संघटनों के निवारण) संशोधन आदेश' की वैधता पर संदेह जताया, लेकिन न्यायालय ने इस विवाद को विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि अधिकारी या न्यायिका जो अधिनियम को प्रबंधित कर रहे हैं, उन्हें विधित्व के खिलाफ आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं हो सकती: के.एस. वेंकटरमन एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम मद्रास राज्य (1)।"

निर्धारिती ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की, जिसमें संविधान के अनुसार धारा 226 के तहत, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1962 के आदेश को केंद्र सरकार के खिलाफ अधिविरेस करने और आदेश के प्रवर्तन की रोकथाम के लिए एक राइट घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने याचिका को नकारा दिया, और यात्री ने इस न्यायालय के द्वारा प्रदान की गई प्रमाणपत्र सहित इस न्यायालय के पास यह अपील की है। इस अपील में यात्री के पक्षकार ने निम्नलिखित विवाद प्रस्तुत किए:

1) 1949 के अधिनियम 67 की धारा 6 ने 'कठिनाई की उत्पत्ति' को आदेश जारी करने की शर्त के रूप में बनाया है, और इसके अनुसार कोई वास्तविकता में कोई कठिनाई का साबित होना चाहिए, क्योंकि विवादित आदेश जारी करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति नहीं थी; उन्हें इस आदेश को जारी करने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा आदेश जारी करने के लिए कोई वास्तविक कठिनाई सामने नहीं आई थी और जिसे वे निरीक्षण कर रहे थे, उस पर विवाद नहीं था। केंद्र सरकार के पास इस विवादित आदेश को जारी करने की शक्ति नहीं थी।

2) यह कि 1949 के अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, केंद्र सरकार को आयकर अधिनियम, 1922 की योजना और मुख्य प्रावधानों के संग संगत आदेश जारी करने की अधिकारिता है, और क्योंकि विवादित आदेश आयकर अधिनियम की योजना और मुख्य प्रावधानों में संशोधन करने के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह कार्य अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अतिरिक्त है।

3) यह कि यदि धारा 6 का व्याख्यान किया जाता है जो केंद्र सरकार को आयकर अधिनियम में संशोधन या परिवर्तन करने की अधिकारिता प्रदान करता है, तो यह माना जाता है कि यह अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अतिरिक्त है, क्योंकि यह विधायिका शक्ति की अत्यधिक देन की बात होती है।

4) यह कि 1922 के आयकर अधिनियम का पुनर्निर्धारण 1961 के आयकर अधिनियम, अधिनियम की धारा 43 के अनुभाग (2) के तहत की जाने वाली विधियों के अनुसार होना चाहिए; और

5) यह कि आयकर प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए आयकर के आदेश या जिन्हें उन्हें जारी करने का इरादा है, वे संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।

1962 का आदेश अमान्य है, क्योंकि धारा 6 के तहत शक्ति का आह्वान के लिए कोई "कठिनाई" साबित नहीं की गई है, जो इसे निराधार करती है। हम बची रही विवादों पर हमारे विचार व्यक्त नहीं करने का प्रस्तावना नहीं करते।

भोपाल के राजा के साथ समझौते के अनुसार, या योग्यता के आधार पर, आयकर कानूनों के प्रयोग से यहां निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि आसंख्यी ने आमदनी–कर अधिनियम के लिए आवश्यक आदान–प्रदान की गई थी। आयकर विभाग के विरुद्ध उपाय किए नहीं गए, ना कोई मुख्यता के आधार पर कोई प्रक्रिया चलाई गई और ना ही आयकर अधिनियम के लिए आसंख्यी को विवाद करने के लिए कोई मान्यता दी गई। इस महकौशल संविधान ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1949 के आदेश के पैराग्राफ 2 में "एक मर्ज़ किए गए राज्य के कानूनों या नियमों के अधीन वास्तविक रूप से प्रदत्त सभी खपत को देखते हुए दी गई जितनी भी विलयित राज्य" व्यक्तिगत अर्थ नहीं दिया जा सकता। यह कोई भी कानून या नियम की प्रावधानिकता के तहत अनुमति दी गई नहीं थी: यह एक विचार को सूचित करता था कि यह अनुमति वास्तविकता को लागू करने का विचार नहीं किया गया था, जिसे कानून या नियमों के दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी गई थी।

आयकर अधिनियम, 1922 के विस्तार के द्वारा, निसंगत रूप से कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं, क्योंकि आयकर अधिनियम, नियम और उनके तहत बनाए गए आदेश ब्रिटिश भारत में प्रचलित परिस्थितियों के विशिष्टताओं को ध्यान में रखते थे, जो एकवर्गीकृत राज्यों में नहीं थीं और नहीं हो सकती थीं। इसलिए, इसे इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक यांत्रिकी बनाने की आवश्यकता थी। इसे इस प्रयास की गई जोर देकर प्राप्त किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार को उसके लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। हालांकि, यह शक्ति उसे प्रयोग करने के लिए थी, जिसमें आवश्यक माना जाता है कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रावधान या निर्देश दिए जाने चाहिए, और और नहीं। आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2)(वी) प्रावधान (क) के साथ धारा 10(5) के साथ पढ़ी गई, व्यापार कर रहे व्यक्ति की आमदनी और लाभ की गणना में अनुमति दी जाने वाली खपत को गणना करने के लिए उन सभी अनुमतियों को जो भारतीय आयकर अधिनियम या उसके द्वारा रद्द किए गए किसी भी अधिनियम या भारतीय आयकर अधिनियम, 1886 के तहत नियुक्त की गई थीं या

उनके तहत नियुक्त की गईं या भारतीय आयकर अधिनियम, 1886 के प्रवृत्ति में जारी किए गए किसी कार्यान्वित आदेश या कार्यान्वित आदेशों के तहत दी गईं गईं थीं, उन्हें मिलाकर गणना की जानी चाहिए थीं। अधिनियम की स्पष्ट शर्तों के अनुसार, किसी भी मौद्रिक वर्ष में लेखा मूल्य निर्धारित करने के लिए केवल उतनी ही खपत को लेना चाहिए था जितनी भारतीय आयकर अधिनियम या उसके द्वारा रद्द किए गए किसी भी अधिनियम या भारतीय आयकर अधिनियम, 1886 के तहत वास्तविक रूप से अनुमति दी गई थी, और क्योंकि एकवर्गीकृत राज्यों के आयकर अधिनियम ने नहीं भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 द्वारा, बल्कि आद्याद्वार नंबर 21, 1949 और अधिनियम 67, 1949 द्वारा रद्द किए गए थे, इसलिए एक मर्जित राज्य में किसी आसंख्यी के इमारतों, मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर के लेखा मूल्य की गणना के लिए विलयित राज्यों के अधीन खपत की अनुमतियों को नहीं लिया जा सकता था। यह एक मर्जित राज्यों में अभिलेखधारितों को एक लाभ प्रदान किया जिससे एक मर्जित राज्यों के नियम के संरचना से अनुसंधित था। केंद्र सरकार ने फिर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि इसके बाद, 1949 में आयकर कानून (विलीन राज्यों) (कठिनाइयों के निवारण) आदेश जारी किया था, और इसके अनुसार आयकर और सुपर-टैक्स से संबंधित किसी भी विलीन राज्य के कानून या नियमों के तहत वास्तविक रूप से अनुमति दी गई खपत को लेना चाहिए था जो उपधारा 10(2)(वी) के प्रावधान (क) के उपशाखा (2) के वि. (vi) के प्रोविजो से संबंधित कुल खपत भत्ते की गणना में संदर्भित हुआ था। आदेश की भाषा स्पष्ट थी। यदि किसी विलीन राज्य के आयकर और सुपर-टैक्स से संबंधित कोई भी खपत वास्तविक रूप से अनुमति देती थी, तो इसे लेखा मूल्य निर्धारित करने में शामिल किया जाना चाहिए था। वास्तविक रूप से अनुमति दी गई खपत ने यह नहीं सूचित किया कि अगर राज्य कानून के तहत निबंधित किया गया होता, तो वह अनुमति दी गई होती, परंतु वास्तविक में नहीं होती। यह इस मामले में इस विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था कि "वास्तविक रूप से अनुमति दी गई खपत" व्यापारिक एक ऐसे मामले में भी ऐसे ही व्याख्यान किया गया था जिसमें कोई राजा एक पार्ट बी राज्य के शासक के साथ एक समझौते के तहत छूट प्राप्त की थी आयकर के भुगतान से मुक्त किए जाने वाले थे, और राज्य के विलय के बाद केंद्र सरकार ने इस समझौते को प्रभावित किया एक सूचना के द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अनुसार धारा 60ए के तहत: कमीशनर ऑफ इनकम-टैक्स, बॉम्बे बनाम धरमपुर लेदर क्लोथ कंपनी लिमिटेड (1), यह भी भारतीय अदालतों ने निर्धारित किया है- और हमारे निर्णय में यह दृष्टिकोण सही है कि संपत्ति की लेखा मूल्य की गणना करते समय उधार नहीं बल्कि वास्तविक रूप से अनुमति दी गई खपत को ध्यान में लेना चाहिए, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अनुसार उपधारा 10(2)(वी) के तहत, जब वह उपशाखा 1941 के अधिनियम 23 द्वारा संशोधित किया गया था: कमीशनर ऑफ इनकम-टैक्स बनाम कमला मिल्स लिमिटेड, वांखदम लक्ष्मीनारायण बनाम आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश (3)।

इसलिए "वास्तविक रूप से अनुमति दी गई खपत" धारा 10(2)(वी) के तहत आयकर अधिनियम में, निकास 1949 के क्लॉ। (2) के तहत और आयकर अधिनियम के धारा 60A के तहत सूचना के तहत कार्य करने से होने वाली कार्यवाही के आय का मूल्यांकन करने के लिए लिए गई खपत का अभिप्रेत होता है, और यह नहीं अर्थ की उधार नहीं बल्कि केवल वर्तमान आयकर प्रावधान के अनुसार अनुमति प्राप्त किया जाने वाला या लागू होने वाला खपत।

लेकिन यह विवादित आदेश उस अर्थ को बदलने का प्रयास करता है। यहां अभियुक्त क़रार किया गया है कि कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई या उत्पन्न हो सकती थी जिससे भारतीय आयकर अधिनियम के तहत विलय राज्यों में खपत की अनुमति के प्रावधानों के प्रभावी रूप से पालन करने में कठिनाई हुई हो, जिसके बाद 1949 के कर विधियों के प्रावधानों को लागू करने के लिए उन्हें विकसित नहीं होने चाहिए था और केंद्र सरकार ने, धारा 67 के अधिनियम के तहत विवादित आदेश जारी करते समय, उन्हें ऐसी शक्तियों को नहीं प्राप्त किया जिन्हें अधिनियम

ने दिया नहीं था, और इस बजह से आदेश अमान्य है। भारत संघ इस दावे का विरोध करता है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1962 का आदेश जारी किया होने के बाद, यह माना जाना चाहिए कि धारा 67 के अधिनियम के प्रावधानों को पालन करते समय समस्याएं उत्पन्न हुई थीं और केंद्र सरकार की इस बार में की गई राय आधारभूत थी। अदालत ने टिप्पणी की:

> "इस धारा की भाषा स्पष्ट रूप से दिखाती है कि यह केंद्र सरकार के लिए है कि क्या कोई ऐसी बाधा या रुकावट है जो ऐसे आदेश की आवश्यकता को बुलाती है जो धारा 6 में संदर्भित अधिनियम, नियम या आदेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए हो। संशय नहीं कि धारा 6 व्यक्त रूप से नहीं कहती कि केंद्र सरकार को यह निर्धारित करना चाहिए कि किसी "मुश्किल" की "मौजूदगी" के बारे में संतुष्ट होना चाहिए, जिसके हटाने के लिए एक आदेश की आवश्यकता है। लेकिन यह धारा 6 की भाषा में स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार में निहित है का आदान–प्रदान करना चाहिए कि किसी अधिनियम, नियम या आदेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई है। यदि किसी "कठिनाई" की मौजूदगी का आधार केंद्र सरकार की संतुष्टि पर निर्भर करता है, तो यह अनुसरण करता है कि किसी भी "कठिनाई" के अस्तित्व की स्थिति, जिसे हटाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश जारी करने की अधिकारी करने वाली है, की सुयय रूप से निर्धारित की जाने वाली व्यक्तिगत स्थिति है जिसे केवल केंद्र सरकार के अलावा कोई नहीं निर्धारित कर सकता है, जिसे इस स्थिति में कार्रवाई करनी हो।"

इस रूप में उच्च न्यायालय ने जिस रूप में टिप्पणी की है, हमारे न्यायिका में यह स्पष्ट त्रुटि थी। किसी भी अधिनियम, नियम या आदेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में उत्थित किसी कठिनाई के अस्तित्व से केंद्र सरकार के द्वारा प्रावधान बनाने या निर्देश जारी करने की शक्ति पर शर्त बनाई गई है। इस धारा ने कठिनाई के उत्थान को सरकार की व्यक्तिगत संतुष्टि के मामले में नहीं बनाया है: यह एक शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व–शर्त है और यदि शर्त के अस्तित्व पर चुनौती दी जाए, तो यह एक वास्तविक तथ्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई ध्यानदेनीय टिप्पणियों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई आदेश के लिए जिस पर आधार रखा गया था, उसे इस मुद्दे पर आपत्ति नहीं है कि "कठिनाई का उत्थान होना" केंद्र सरकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का विषय है। दीवान बहादुर राजगोपाल मिल्स केस में, ("), इस विभाग से यह विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या टैक्सेशन लॉज पार्ट बी स्टेट्स) (कठिनाई के निवारण) आदेश, 1950 के पैराग्राफ 2 की वैधता है। उस केस में आपत्तिकर्ता ने यह दावा किया कि जो मई 8, 1956 को जारी की गई सूचना S.R.O. 1139 जो 1950 के फाइनेंस एक्ट की धारा 12 के अनुसार विधित थी, जिसे मूल रूप से साक्षात रूप से धारा 6 के अनुसार समान शब्दों में लिखा गया था, वह अवैध था। इस विभाग ने इस दावे को नकारते हुए यह आदेर्श दिया कि क्लॉस (बी) के उप–अनुभाग (5) की विधियों का प्रावधान लागू करते समय एक पार्ट बी राज्य में एक आसदार के लिए प्राथमिक कठिनाई थी, क्योंकि पार्ट बी राज्यों में लागू कानूनों को भारतीय आयकर अधिनियम ने नहीं रद्द किया था, बल्कि यह वित्त, एक्ट, 1950 ने किया था, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए टैक्सेशन लॉज (पार्ट बी राज्य) (कठिनाई के निवारण) आदेश, 1950 पारित किया गया था।

इस आदेश को आयकर अधिनियम की धारा 60A के तहत संघ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधित किया गया था, लेकिन यह संशोधन हैदराबाद की उच्च न्यायालय ने अत्यधिकारी ठराया, और इसके बाद 1956 में एक और कठिनाई के निवारण आदेश जारी किया गया, जिसमें स्पष्टीकरण को पुनराच्छादित किया गया। यह महकमा

ने धारा 60A के अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश 1950 के द्वारा अनूठी परिणाम होते हैं, और भारतीय आयकर अधिनियम के तहत आसदार को मिली खपत छूट से अधिक थी। हैदराबाद आयकर अधिनियम के तहत खपत छूट का अधिकार था, और इसे दूर करने के लिए आवश्यक था कि 1956 के कठिनाई के निवारण आदेश जारी किया जाए। महकमे के दृष्टिकोण से, उस मामले में सत्त्वयित अधिविशेष अभ्यर्थन के लिए शक्तियों के प्रयोग के लिए प्रावधानिक शर्त उपस्थित थी। स. 12 के तहत वित्त एक्ट के अधिनियम के आदेश द्वारा निकाले गए कठिनाई की आवश्यकता होने पर महकमे ने यह टिप्पणी की:

> "इसके अलावा, धारा की सही व्यापकता और प्रभाव यह लगता है कि यह केंद्र सरकार के लिए है कि क्या कोई कठिनाई उत्पन्न हुई है और फिर इस कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने, या ऐसे निर्देश देने की स्वीकृति देने की आवश्यकता है। संसद ने इस मामले को कार्यपालिका के लिए छोड़ दिया है, लेकिन यह नहीं कहती कि 1956 की अधिसूचना बुरी है।"

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन टिप्पणियों पर आश्रित होकर निर्धारित किया कि केंद्र सरकार का निर्णय कि कोई कठिनाई उत्पन्न हुई थी, सरकार के अंदर विषयिक संतोष की एक मामला थी, और यह मामला न्यायिक परिषदों के लिए जांचने के लिए नहीं खुला था। हम नहीं मानते कि यह संविवादों के वह विवरणों की उन्हें उस व्याख्या के लिए अधिक भावुक करने योग्य हैं। यह इस से स्पष्ट है कि इस सीरिज की टिप्पणियों से इस संदर्भ में न्यायिक द्वारा सत्यापित किया गया कि वास्तव में कठिनाई उत्पन्न हुई थी और उसे हटाने के लिए 1956 का आदेश जारी किया गया था। प्राथमिकता रखी गई थी कि यह यहाँ उल्लिखित किया गया था कि अधिकारी द्वारा दायित्व प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने में कोई कठिनाई नहीं आई थी, न तो 1922 के भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई आई थी, और न ही पहले आदेश के प्रावधानों को लागू करने के लिए संघीय राज्यों के अधिनियम के अनुसार धारा 6 के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने की कोई समस्या थी। उत्तरदाताओं की ओर से यह जवाब दिया गया था कि "प्रार्थियों के पक्ष से उठाई गई यह दावा गलत है और इसलिए इसे नकारा किया गया है"। उत्तरदाताओं की ओर से दिए गए इस उक्तिकरण के अनुसार, जवाब में वित्त विभाग के सचिव द्वारा बनाई गई एक "लेखन" को पढ़ा गया जिस पर केंद्र सरकार को 1962 का आदेश जारी करने के लिए प्रेरित किया गया था। लेकिन वह "लेखन" बस यह कहता था कि भारत में उच्च न्यायालयों ने नकारत्मक किया कि आयकर विभाग का दावा माना जाए जिसमें कहा गया था कि उन मामलों में जहां व्यापार के संबंध में निर्धारित करना था कि जो कारण एक यात्रा के साथ किए गए एक समझौते के तहत भारतीय राज्य के शासक से किया गया था, उन्हें आयकर भरने से छूट दी गई थी, उसमें वियतन के मान का लेखावलोकन किया जाना चाहिए जो मना किया गया था, यदि उन्हें कर भरने का आदान–प्रदान किया गया होता, उसे निधारित करने के लिए देखना चाहिए कि धन्यवादी की लिखित मूल्य को किस परिस्थिति में मान लिया जाए, जिस पर आयकर अधिनियम को लागू किया गया था। कानून के साफ शब्दों के खिलाफ उठाए गए आयकर विभाग के पक्ष से उठाए गए एक दावे को स्वीकार करने से न्यायिक नकार करना इसे नहीं माना जा सकता कि कानून के प्रावधानों के प्रभावी रूप से प्रयोग में कठिनाई आई है। आदेश में विचारित कठिनाई का कारण नहीं सिर्फ केवल यह है कि केंद्र सरकार की असमर्थनता है कि कर योग्यता विधिनिष्ठ विधानन निर्धारित की जा सकती थी, जो सरकार के दृष्टिकोण से करदाता ने देने के लिए किया हो लेकिन जिसे उचित विधानन द्वारा लागू नहीं किया गया था। सॉलिसिटर–जनरल ने यह दावा किया कि धारा 10 उप–धारा (5) (बी) के शर्तों के आधार पर आयकर अधिनियम का लागू करने में भारतीय आयकर अधिनियम के लिए पहली बार आवेदन किया गया था, इससे मिलने वाली एक कठिनाई मुद्दा उत्पन्न हुआ क्योंकि सम्मिलित राज्यों में करदाता द्वारा प्राप्त निर्धारित की जा सकने वाली कोई लिखित मूल्य नहीं निर्धारित की जा सकती थी, जो आय के वर्ष से पहले आसन्न संबंधी होने वाले वर्ष के लिए हो सकती है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए निश्चित संपत्ति का लिखित मूल्य को कैसे निर्धारित

किया जा सकेगा। वकील ने धारा 2 (2) और धारा 10 (1) में "असेसीज़" की परिभाषा पर आधारित करके दावा किया कि क्योंकि धारा 10 के उप–धारा (5) के अनुसार श्रेणी (ए) में पिछले वर्ष में प्राप्त संपत्ति के संबंध में वास्तविक लागत असेसीज़ के लिए लिखित मूल्य होगा, और श्रेणी (बी) में पिछले वर्ष से पहले प्राप्त संपत्ति के मामले में लिखित मूल्य के रूप में असेसीज़ के लिए लागू की गई सभी निर्धारित की गई विघटन से न्यायिकी लाभ उपभोक्ता के लिए वास्तविक लागत होगी, और श्रेणी (बी) के अनुसार जो संपत्ति पिछले वर्ष से पहले प्राप्त की गई है, उनके लिए वास्तविक लागत होगी, और अधिनियम के तहत उन्हें वास्तविक लाभ की गई सभी विघटन से कम वास्तविक लागत होगी, तो जो व्यक्ति अपनी कर योग्य आय की गणना में विघटन भालूनी दावा करने के लिए नास्तिक योग्य होता है, उसे भारतीय आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किए जाने वाले किसी भी वर्ष में प्राचीन साल से पहले एक असेसीज़ होना चाहिए: अगर वह करदाता नहीं था तो प्रधान विभाग 10 के उप–विभाग (5) (बी) के बी का निर्धारण किया जा सकता था। मुख्य वकील ने यह दावा किया कि विवादित आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था ताकि अधिनियम के प्रशासन में उस कठिनाई को हटाया जा सके। हमारी न्याय में, यह तर्क पूरी तरह गलत है। धारा 10 के उप–विभाग (5) केवल एक परिभाषा श्रेणी है: यह निर्धारण की बात नहीं करता है कि नुक्सान की मात्रा कैसे निर्धारित की जाए। "दीर्घकालिक निगमन" के संबंध में नुकसान की मात्रा आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) (vi) के अंतर्गत दी गई छूट के अनुसार निर्धारित होती है। उस परिवर्तन के तहत, जिसे 1949 के आदेश ने किया, आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) (vi) का अनुसरण करते हुए उसमें संशोधन किया गया, और सम्मिलित राज्यों के कानून के अनुसार वास्तविक रूप से दी गई छूट को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो धारा 10 (2) (vi) के प्रोविसो के उप–विधि (c) में उल्लिखित नुकसान भालूनी में दी गई छूट को ध्यान में रखने के लिए किया गया था। धारा 10(5) के उप–विभाग (बी) के उपयुक्त शब्दों का संयोजन साथ ही 1949 के आदेश के साथ, इस पर आधारित होकर संयुक्त राज्यों में करदाता की संपत्ति की लिखित मूल्य निर्धारित नहीं की जा सकती है, और उस कठिनाई को दूर करने के दृष्टि से विवादित आदेश प्रचारित किया गया था। यह तथ्य कि संपत्ति को एक व्यक्ति ने वह समय अधिकारित के रूप में नहीं प्राप्त किया था जब वह भारतीय आयकर अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत कोई करदाता नहीं था, उसे विकास के समय पर कर पर मूल्यांकन करने से नहीं वंचित करेगा, जब उसे व्यापार के लाभ पर कर लगाया जाता है, तो उसे उन संपत्तियों के लाभ का दावा करने से वंचित नहीं करेगा जो व्यापार के उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हों।

अधिनियम 67 के धारा 6 के अनुसार, केंद्र सरकार को किसी भी ऐसे प्रावधानों को लागू करने या मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होने पर अधिकार है जो किसी भी अधिनियम, नियम या आदेश के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को हटाने के लिए आवश्यक लगे। धारा 3 द्वारा संघित राज्यों में बढ़ाए गए किसी भी अधिनियम, नियम या आदेश के प्रावधानों को प्रासंगिक बनाने के लिए किए गए आवेदन से कठिनाई उत्पन्न हुई थी। भारतीय आयकर अधिनियम के लागू होने से जुड़े सम्मिलित राज्यों में व्याप्ति के समय कठिनाई उत्पन्न हुई थी जिसमें धारा 10(2) (vi) के तहत निर्धारित नुकसान भालूनी का मामला शामिल था। उस कठिनाई को 1949 के कर विधि (संघित राज्य) (कठिनाईयों का निवारण) आदेश के पास से हटाया गया था। उस आदेश द्वारा निर्धारित किया गया कि एक संघित राज्य के किसी भी कानून या नियमों के अंतर्गत वास्तविक रूप से दिया गया निर्धारित नुकसान भालूनी को लेना चाहिए जो आयकर से संबंधित था। इसके बाद भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों को या जो नियम या आदेश धारा 3 द्वारा संघित राज्यों में बढ़ाए गए थे, उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने में कोई कठिनाई नहीं बची।

संक्षिप्त करने के लिए: अधिनियम 67 के धारा 6 द्वारा प्रादान की गई शक्ति एक कठिनाई को हटाने के लिए है जो आयकर अधिनियम के संघित राज्यों में लागू होने में उत्पन्न होती है: यह ऐसे प्रकार से प्रयुक्त की जा सकती है जो अधिनियम की योजना और महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ संगत हो और जिसके लिए यह प्रदान किया गया है।

विवादित आदेश जो शक्ति के प्रासंगिक व्यवहार के पूर्वावलोकन के नाम पर एक ऐसी कठिनाई को हटाने का प्रयास करता है जो उत्पन्न नहीं हुई थी, इसलिए अधिनियमित नहीं था। हम इस परिस्थितियों में यह मानते हैं कि इसे किस स्थिति में यह निर्धारित करने की आवश्यकता है, यदि कोई हो, केंद्र सरकार को यह अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कोई प्रावधान करने के लिए अधिदानित करने के लिए अधिनियम 67 के धारा 6 द्वारा प्रादान की गई शक्ति। हमें यह भी नहीं लगता कि इस पर निर्भर करने की कोई आवश्यकता है, कि क्या केंद्र सरकार को इसके द्वारा जारी किए गए किसी आदेश से कितने हिस्से तक, यदि कोई, भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने पर किस प्रमाण में खुला होगा। हमें यह भी नहीं कहने की आवश्यकता है कि क्या आदेश, यदि कोई, क्या 1961 के भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 298 के तहत जारी किया गया था, या क्या इस आदेश के अधिनियम की धारा 298 के तहत जारी होने के कारण कोई भी समानता की गारंटी उल्लंघन हुआ था, इस पर कोई राय देने की आवश्यकता नहीं है।

अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। यह घोषित किया जाता है कि सी.एल. (बी) कराधान कानून (विलयित राज्य) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1962 में स्पष्टीकरण, धारा के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय केंद्र सरकार के अधिकार के बाहर है। 1949 के अधिनियम 67 के 6 और राजस्व अधिकारी आदेश में उस खंड के अनुसार गणना किए गए मूल्यह्रास भत्ते के आधार पर कर लगाने के हकदार नहीं हैं। निर्धारिती को इसकी लागत इस न्यायालय और उच्च न्यायालय में उत्तरदाताओं से मिलेगी।

जीसी अपील की अनुमति दी गई|

विक्रांत ठाकुर की देखरेख में महेश कुमार राठौर द्वारा अनुवादित।